बिहार सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

अधिसूचना

संख्या-पर्या0/वन-25/2018...../प0व0 पटना-15, दिनांक-....

चूँकि प्लास्टिक कैरी बैग पर्यावरण के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक नुकसान तथा स्वास्थ्य परिसंकट के कारक हैं;

और चूँकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 48-क, अन्य बातों के साथ-साथ परिकल्पित करता है कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए प्रयास करेगा;

और चूँिक यह देखा गया है कि प्लास्टिक कैरी बैग जैव-विघटेय नहीं हैं, जलने से विषाक्त गैसों का उत्सर्जन करते हैं, मलनालियों एवं नालियों को अवरूद्ध करते हैं, मृदा की उर्वरा शिक्त क्षीण करते हैं तथा खाद्य पदार्थों के साथ प्लास्टिक अपिशष्ट खा लिये जाने से जानवरों के जीवन को खतरा उत्पन्न करते हैं;

और चूँिक प्लास्टिक कैरी बैग से सामान्य रूप से पर्यावरण एवं विशेष रूप से स्थानीय पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर विचार करते हुए बिहार सरकार ने महसूस किया है कि प्लास्टिक कैरी बैग पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं;

इसलिए, अब, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 के अधीन प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निर्गत अधिसूचना सं0 एस0ओ0 152 (ई0) दिनांक 10.02.1988 द्वारा इस राज्य को प्रत्यायोजित शिक्तयों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार इस अधिसूचना के माध्यम से राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत की परिसीमा के भीतर प्लास्टिक कैरी बैग (उनके आकार एवं मोटाई का विचार किए बिना) के विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के पश्चात्, पूर्ण प्रतिबंध लगाती है। इस संदर्भ में बिहार सरकार निम्नलिखित निर्देश जारी करती है:-

निर्देश:

 कोई भी व्यक्ति, राज्य के नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत की अधिकारिता में प्लास्टिक कैरी बैग (उनके आकार एवं मोटाई का विचार किये बिना) का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग नहीं करेगा। 2. बिहार राज्य के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के अधिकारिता में कोई भी व्यक्ति, जिसमें दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, व्यापारी, फेरीवाला अथवा सब्जीवाला आदि सम्मिलित हैं, प्लास्टिक कैरी बैग का विक्रय अथवा भंडारण अथवा वितरण अथवा खाद्य पदार्थ या गैर-खाद्य/सामग्रियों के भंडारण अथवा प्रदाय के लिए उपयोग नहीं करेगा।

अपवाद:

जीव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अधीन यथाविनिर्दिष्ट जीव-चिकित्सा अपशिष्टों के उचित निपटान हेतु इनके संग्रहण/भंडारण के लिए प्लास्टिक कैरी बैग (50 माइक्रोन्स से अधिक मुटाई वाले) के उपयोग को एतद् द्वारा छूट दी जाती है। राज्य सरकार को आकलन के आधार पर इस अधिसूचना के तहत किसी अपवाद का प्रावधान करने का अधिकार आरक्षित है। खाद्य पदार्थों के पैकेजिंग, दूध एवं दूध उत्पादों तथा पौधशालाओं में पौधा उगाने हेतु प्रयुक्त होने वाले प्लास्टिक पात्रों को कैरी बैग नहीं माना जायेगा।

स्पष्टीकरण:

इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ ''प्लास्टिक की थैलियों'' का वही अर्थ होंगे जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत प्लास्टिक अपिशष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 में परिभाषित है जिसे निम्न रूप में पुन: प्रस्तुत किया जाता है:-

''प्लास्टिक की थैलियों'' का तात्पर्य वस्तुओं को ले जाने या वितरण के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक सामग्री से निर्मित किसी प्रकार की थैली से है लेकिन इसमें वे थैलियाँ शामिल नहीं हैं, जो पैकेजिंग का भाग या हिस्सा बनती है या इसका अभिन्न अंग है, जिसमें प्रयोग से पूर्व वस्तुएँ सीलबन्द की जाती हैं।

प्राधिकृत पदाधिकारी :

निम्नलिखित अधिकारियों को एतदद्वारा उनकी अधिकारिता में इस अधिसूचना को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है :-

- 1. प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार।
- 2. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार।
- 3. अध्यक्ष एवं सदस्य-सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्।
- 4. जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक अपनी अधिकारिता की बाबत।
- 5. अनुमंडल दण्डाधिकारी/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपनी अधिकारिता की बाबत।
- 6. नगर आयुक्त, नगर निगम की बाबत।
- 7. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत की बाबत।

- 8. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 421 और 422 के अधीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित बनाई गई उप विधियों (Bye-laws) में प्राधिकृत पदाधिकारी/कार्यबल
- क्षेत्रीय पदाधिकारी/सहायक पर्यावरण अभियंता/वैज्ञानिक, सहायक वैज्ञानिक पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्।
- 10.सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र अपनी बाबत।

अनुश्रवण:

अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् एवं प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा इन निर्देशों का सम्पूर्ण रूप से अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत प्राधिकृत पदाधिकारी इस निर्देश की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध परिवाद वाद दाखिल करने के लिए प्राधिकृत होंगे।

दण्डात्मक प्रावधान :

इन निर्देशों का उल्लंघन, पर्यावरण (संरक्षण)अधिनियम, 1986 की धारा-15 के दण्डात्मक प्रावधान को आकृष्ट करेगा और ऐसे अपराध से कारावास, जिसे 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा या ऐसे जुर्माने से जिसे एक लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

किसी भी निर्देश के उल्लंघन की स्थित में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-421 एवं 422 के अन्तर्गत बनाये गये उप-विधियों के अनुरूप जप्ती, जुर्माना, अपराधशमन इत्यादि की कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रवर्त्तन :

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के पश्चात् प्रवृत होगी। इसी 60 दिनों की अविध के भीतर सभी व्यक्ति जिसमें विनिर्माता, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता तथा प्लास्टिक केरी बैग के व्यापारी एवं दुकानदार, विक्रेता, फेरीवाला, सब्जीवाला शामिल हैं, के द्वारा प्लास्टिक केरी बैग के भण्डार का निपटारा कर लेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/(त्रिपुरारि शरण)
प्रधान सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
बिहार सरकार

ज्ञापांक — पर्या0/वन-25/2018/प०व० पटना—15, दिनांक :
प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
ह 0 / — (त्रिपुरारि शरण) सरकार के प्रधान सचिव
ज्ञापांक — पर्या0/वन-25/2018/प०व० पटना—15, दिनांक :
प्रतिलिपिः अवर सचिव, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को (सी०डी० एवं हार्ड कॉपी सहित) बिहार राजपत्र के अगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशनार्थ।
2. इसकी 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियों पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।
ह0 ∕ −
(त्रिपुरारि शरण) सरकार के प्रधान सचिव
ज्ञापांक — पर्या0/वन-25/2018/ प०व० पटना—15, दिनांक :
प्रतिलिपिः महामिहम राजयपाल के सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद/ सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद/माननीय उप मुख्य (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन) मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान अप्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
₹0 / −
(त्रिपुरारि शरण) सरकार के प्रधान सचिव
ज्ञापांक — पर्या0/वन-25/2018/प०व० पटना—15, दिनांक :
प्रतिलिपिः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/सभी अपर प्रधान वन संरक्षक, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
ह0 ∕ −
(त्रिपुरारि शरण) ् सरकार के प्रधान सचिव
चापांक— पर्या0/वन-25/2018 1153 (\$%) प०व० पटना—15, दिनांक : 15 10 18
प्रतिलिपिः आई0टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
(त्रिपुरारि शरण) सरकार के प्रधान सचिव

GOVERNMENT OF BIHAR Department of Environment, Forest & Climate Change

NOTIFICATION

No.Parya Van-25/2018...../E.F., Patna-15, Dated-

Whereas, plastic carry bags cause short term and long term environmental damage and health hazard;

And Whereas, Article-48A of the Constitution of India, inter alia, envisages that the State shall endeavour to protect and improve the environment;

And Whereas, it is observed that plastic carry bags are non-biodegradable, produce toxic gases on burning, causes choking of sewers and drains, reduces soil fertility and pose threat to the life of cattle, eating plastic wastes along with their feed;

And Whereas, the Government of Bihar after considering the adverse effects of plastic carry bags on the environment in general and local ecology in particular felt that plastic carry bags have detrimental effects on the environment and human health;

Now therefore, in exercise of the powers delegated to this state under the Notification No- S.O.-152(E) dated 10.02.1988 issued under section 5 of the said Act by the Environment, Forest and Climate Change Ministry, Government of India exercises the powers conferred under section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) the Government of Bihar issues this notification to impose a complete ban on the manufacture, import, store, transport, sale and use of plastic carry bags (irrespective of their size and thickness) in the jurisdiction of all the Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats in the State of Bihar after 60 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette. In this context, the Government of Bihar hereby issues the following directions namely:-

Directions:

- 1. No person shall manufacture, import, store, distribute, sell, transport or use any kinds of plastic carry bags (irrespective of their size and thickness) in the jurisdiction of all the Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats in the State of Bihar.
- 2. No person including a shopkeeper, vendor, wholesaler, retailer, trader, hawker, *feriwala* or *sabjiwala* shall sell or store or distribute or use any kind of plastic carry bags for storing or

dispensing of any eatable or non-eatable goods or materials in the jurisdiction of all the Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats in the State of Bihar.

Exceptions:

The use of plastic carry bags (above 50 microns thickness) only for collection/ storage of Bio-Medical Waste for its disposal as specified under the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 is hereby exempted. State Government reserves the right to provide for any exception under this notification based on its assessment. The plastic containers used for packaging of food materials, milk and milk products and raising plants in the nurseries shall not be deemed as carry bags.

Explanation:

For the purpose of this Notification "Plastic carry bags" shall have the same meaning as defined in the Plastic Waste Management Rules, 2016, issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India which is reproduced below:-

"Carry bags" mean bags made from plastic material, used for the purpose of carrying or dispensing commodities which have a self carrying feature but do not include bags that constitute or form an integral part of the packaging in which goods are sealed prior to use.

Authorized Officers:

The following officers are hereby authorized to implement this notification in their respective jurisdiction namely:-

- 1. The Principal Secretary, Environment and Forest Department, Government of Bihar;
- 2. The Principal Secretary, Urban Development & Housing Department, Government of Bihar;
- 3. The Chairman or the Member Secretary, Bihar State Pollution Control Board;
- 4. The District Magistrate and Superintendents of Police in respect of their jurisdiction;
- 5. The Sub-Divisional Magistrate/Sub-Divisional Police Officers in respect of their jurisdiction;
- 6. The Municipal Commissioners in respect of Municipal Corporations;
- 7. The Executive Officers in respect of Municipal Councils and/or Nagar Panchayats;

- 8. The persons/task force authorised in the Bye-laws related to Plastic Waste Management made under sections 421 & 422 of the Bihar Municipal Act, 2007.
- 9. The Regional Officers/AEEs/Scientists/ASOs of Bihar State Pollution Control Board;
- 10. All General Managers, District Industries Centre in respect of their jurisdiction;

Monitoring:

The Chairman, Bihar State Pollution Control Board and the Principal Secretary, Urban Development and Housing Department, Government of Bihar shall ensure monitoring and implementation of these directions. The authorized officers under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 shall file complaint in case of violation of these directions.

Penalty:

The contravention of any of these directions shall attract penal provisions of section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986 and is punishable with imprisonment for a term which may extend to five years or with fine which may extend to Rs. one Lakh or with both.

In case of violation of any direction seizure and fine may be imposed in accordance with the bye-laws made under section 421 & 422 of the Bihar Municipal Act, 2007.

Enforcement:

This notification shall come into force after 60 days from the date of its publication in the Official Gazette. All persons including manufacturers, wholesalers, retailers and traders of plastic carry bags, shopkeepers, vendors, hawkers, feriwalas and sabjiwalas shall dispose of their stock of plastic carry bags within this 60 days period.

By the order of the Governor of Bihar

Sd/-

(Tripurari Sharan)
Principal Secretary
Department of Environment, Forest &
Climate Change
Government of Bihar

Memo No.- Parva Van-25/2018...../E.F.. Patna-15, Dated- Copy to Accountant General, Bihar. Patna for information and necessary action. Sd/-(Tripurari Sharan) Principal Secretary to Government **Memo No.-** Parya Van-25/2018...../E.F., Patna-15. Dated- Copy to the Under Secretary, e-gazette cell, Finance Department, Bihar, Patna (along with C.D. and two hard copy) for information and necessary action. He is requested to publish this notification in the next extraordinary issue of Bihar Gazette for the knowledge of general public. Kindly send 500 copies of special Gazette to the Environment, Forest & Climate change Department, Bihar, Patna. Sd/-(Tripurari Sharan) Principal Secretary to Government **Memo No.-** Parya Van-25/2018...../E.F.. Patna-15, Dated- Copy to Secretary to the Governor of Bihar/Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Bihar/Advocate General, Bihar, Patna/chief Secreary, Bihar/ All Principal Secretary & Secretary/All Head of the Departments/All Divisional Commissioners/ Chairman, Bihar State pollution Control Board, Patna/ member Secretary, Bihar State pollution Control Board, Patna/Private Secretary to the Hon'ble Deputy Chief (Environment, Forest and Climate Change) Minister/ Principal Private Secretary to the Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department and all Officers of Environment, Forest and Climate Change Department for information and necessary action. Sd/-(Tripurari Sharan) Principal Secretary to Government Patna-15, Dated- **Memo No.-** Parya Van-25/2018...../E.F., Copy to Principal Chief Conservator of Forest, Bihar, Patna/Additional Principal Chief Conservator of Forest, Bihar, Patna/All Regional Chief Conservator of Forest/ All Chief Conservator of Forest/ All Conservator of Forest/All Divisional Forest officer for information and necessary action. Sd/-(Tripurari Sharan) Principal Secretary to Government Memo No.- Parya Van-25/2018...\\\53(\mathcal{E}).../E.F.. Patna-15, Dated- 15/19/18. Copy to I.T. Manager, Environment, Forest and Climate Change Department, Bihar Patna for Uploading it on the Departmental Website. the Stolle (Tripurari Sharan) Principal Secretary to Government